पाश की कविता

आज का दिन

लगता है यह सवेर नहीं है
मौत की हथेली पर जमी हुई मुस्कराहट है
रात की रो-रोकर सूजी हुई ऑख है
सूर्य-जैसा कुछ कहीं नहीं है

कबुतरों के गुटकने से कुछ भी शुरू नहीं हुआ
शायद आज का दिन बचने नशेड़ी
की आह से शुरू हुआ है
बिल्ली गिरा गई जिसका
भिगोए पोस्त का छन्ना
आज का दिन शायद करमू की
सूखती जा रही धरती पर उगा है

जिसके खुरली पर बंधे बैल को
रात में सरकारी सांड मार गया था
आज का दिन फटे हुए दूध की चाय-जैसा
विधवा रतनी के गले से मुश्किल से उतरता है
आज का दिन शैदाई हरिकिशन की
गालियों के किनारे लड़खड़ाता चल रहा है
आज का दिन अमरो भंगिन के गले में पहने हुए उतार की तरह
नंगेज की खामोशी तैर रहा है
लगता है आज का दिन किसी मुर्दे का लहू है
या रद्द की गई वोट की पर्ची है
या कि गांव की अल्हड़ लड़की के बहुत कम देख सकनेवाले
नयनों की बहुत गहरी दृष्टि है
या उदास बूढ़े के
सींक खाए दरवाजे की चौखट
पर लगी हुई टिकटिकी है
या किसी बांझ औरत का
चौरस्ते में किया हुआ टोना है

आज का दिन किसी जालिम मंत्री का
अनचाहा दफ्तरी मातम है
या किसी दुर्गंध छोड़ते थैले के भीतर
बुझाकर रखा बीड़ी का टुकड़ा है
या शायद
सातवीं में फेल हुई बच्ची की
चुनरी में रखा सूखी आंखों का नीर है
आज का दिन धार्मिक मान्यता का दिन नहीं है

आज का दिन धार्मिक मान्यता का दिन नहीं है
किसी बच्चे की बड़बड़ाती नींद है
आज का दिन तो संभाल-संभालकर पाला
हुआ आतंक का वृक्ष है
राजनीतिक हिंसा की श्रृगारी हुई घोड़ी है
आज का दिन किसी दुश्मन द्वारा
खेतों में दी गई चुनौती है

आज का दिन किसी ग्रंथी के
शंख बजाने से खत्म नहीं होगा
आज का दिन शायद बहुत लंबा चला जाए
और पंक्षी संध्या की उड़ान की प्रतीक्षा में थक जाएं
आज का दिन शायद बहुत लंबा चला जाए।

पेज 1 का शेष भाग

ईएसआई अस्पताल की मुक्ति

जो रहना भी चाहते हैं, वे भी अत्याधिक बढ़े कार्यभार की वजह से यह सब ईएसआई निगम के अधिकारियों की बदनीयती एवं हरामखोरी का नतीजा है कि जिस हस्पताल में 150 डाक्टर व 600 अन्य स्टाफ़ होना चाहिये था वहां आज 17 डॉक्टर व नाम मात्र का ही स्टाफ है। समझने वाली बात यह है कि जब 700 करोड़ की लागत का एक मेडिकल कॉलेज ईएसआई निगम ने खड़ा कर दिया, जिसकी मंजूरी एवं मान्यता के लिए 300 बिस्तर का अस्पताल होना जरूरी है, जिसकी दशा एवं दुर्दशा के आधार पर ही एम सी आई ने मंजूरी प्रदान करनी है तो उसके लिये स्टाफ़ भर्ती पहले से क्यों नहीं किया गया? आग लगने के बाद कुंआ खोदने का क्या मतलब?

जानकार बताते है कि करीब एक वर्ष पूर्व ई एस आई निगम के किसी समझदार अधिकारी ने स्टाफ़ भर्ती के लिए आवेदन आमन्त्रित किये थे, इच्छुक लोगों ने आवेदन दिये भी थे लेकिन फिर किसी नालायक अफ़सर ने वह भर्ती यह कहते हुए रद्द कर दी कि जब अस्पताल मिलेगा तभी भर्ती करेंगे। आज 300 बिस्तर का अस्पताल तैयार है। मरीज बड़ी संख्या में धक्के खा रहे हैं। ये वे मरीज है जिनके वेतन से ईएसआई जबरन 6.5 प्रतिशत वसूल करती है।

स्टाफ भर्ती तो ई एस आई को करनी पड़ेगी क्योंकि एम सी आई से मंजूरी लेनी है, लेकिन कब? तबतक मरीजों का क्या होग? ई एस आई की इस मुर्खता के चलते आज इस अस्पताल की हालत पहले से भी बद्तर हो चूकी है मरीज़ टीके हुए है तो बस एक ही उम्मीद पर कि आने वाले एक दो माह में हालात सुधर जायेंगे।

अस्पताल हस्तानांत्रण की प्रक्रिया वैसे तो कोई बहुत बड़ा एवं कठिन काम नहीं था, क्योंकि इसमें मात्र कुछ दस्तावेजों एवं रीपोंटों का ही आदान-प्रदान होना होता है। यह काम बजरिया डाक बहुत ही बहुत ही सरलता एवं सस्ते में हो सकता है परन्तु इस देश में तो ऐसा कल्चर है नहीं यहां तो एक-एक कागज को एक टेबल से दूसरे टेबल तक धकियाने के लिए पूरा जोड़ लगाना पड़ता है।

इस मामले में भी यदि जोड़ लगाने के लिए दो आदमी दिन-रात इस काम में न जूटते तो यह हस्तान्तरण कम से कम इस वर्ष तो होने वाला था नहीं ये दो आदमी है, मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर दास व डॉ. जसवन्त सिंह यू तो ये दोनों पिछले काफी समय से इस (हस्तान्तरण) प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे, परन्तु पिछले 15-20 दिन तो इन्होंने न रात देखी न दिन अपने खर्चे से वह नौकरी से छुट्टियां ले लेकर चंडीगढ़ व रोहतक तथा दिल्ली के चक्कर पर चक्कर लगाकर जैसे तैसे इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया है। यदि 30 सितम्बर की तारीख निकल जाती तो फिर यह प्रोजेक्ट कम से कम एक साल के लिए ठण्डे बस्ते मे चला जाता इस लिए ये दोनों डॉक्टर बधाई के पात्र है।

देखें मेडिकल कॉलेज एवं ई एस आई प्रबंधन से आम मज़दूर को राहत मिलती है। या सिर्फ़ सारे प्रोजेक्ट का श्रेय हड़पने को आतुर राजनेताओं की बयानबाजी से ही संतोष करना पड़ेगा।

समस्या बार्डर या दिल्ली नहीं, समस्या स्वयं मोदी है

हद तो तब हुई जब मोदी ने सेना में मुसलमानों की संख्या उजागर करने को, साम्प्रदायिक आधार पर सेना को बांटने का कदम बताया। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि एक राष्ट्रीय सेना में किसी एक धर्म का बेहद कम प्रतिनिधित्व राष्ट्र की बुनियाद को ही कमज़ोर करता है। मोदी को यह भी दिखाई नहीं देता कि सेना पहले से ही जातिगत एवं क्षेत्रीयता की अस्मिताओं को ढोती चली आ रही है। मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख एल आई, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट इत्यादि को और क्या कहा जायेगा।

इसी तरह राष्ट्रनिर्माण में सैनिकों के बलिदान का गुणगान करने में नरेन्द्र मोदी ने सारे विशेषण झोंक दिये। सैनिकों के बलिदान की आड़ में वे शायद स्वयं को भी बलिदानी दिखाना चाहते रहे होंगे। कितनी आसानी से नरेन्द्र मोदी भूल जाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जब देश का बच्चा-बच्चा कुर्बानी के लिये तत्पर था तो मोदी जैसों का जनक संगठन आर एस एस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) अंग्रेजपरस्ती की मिसालें पेश कर रहा था। आर एस एस के एक भी सदस्य के बलिदान देने का एक भी उदाहरण न स्वतन्त्रता से पहले है और न ही स्वतंत्रता के बाद।

सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली की गद्दी पर बैठ कर मोदी साहब करेंगे क्या? वही जो सुरक्षा और समृद्धि से घिरे तमाम निरंकुश शासकों द्वारा किया जाता है। भारत की सीमायें 'गर्म' की जायेंगी; दिल्ली में उत्तेजक घोषणायें होंगी और सीमा पर सैनिक मारे जायेंगे। क्या मोदी यह बताना चाहेंगे कि कारगिल में बलिदान हुए करीब एक हज़ार भारतीय सेना के जवानों और अफ़सरों के खून का हिसाब उनकी पार्टी की तत्कालीन केन्द्र सरकार ने आज तक क्यों नहीं दिया? कारगिल में अगर अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद और परवेज मुशर्फ़ के बेटे को सैनिक बना कर लड़ने के लिये भेज दिया गया होता तो दोनों ओर से इतने सैनिकों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। क्योंकि तब युद्ध ही नहीं होता। मोदी अपनी 'मजबूती' गुजरात में दिखा ही चुके हैं। उनके गुर्गे डीआईजी वनजारा ने उन पर झूठी मुठभेड़ों में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनके नेतृत्व में 2002 के गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के कारण इस देश में अलकायदा जैसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन पैर जमा सके हैं। मोदी के केन्द्र की गद्दी सम्भालने और 'मजबूती' दिखाने के बाद क्या भारत का हाल भी पाकिस्तान वाला नहीं हो जायेगा, जहां हर रोज़ बम विस्फ़ोटो और हिंसक वारदातों का निरन्तर सिलसिला वहां की सरकारों के काबू से बाहर हो चुका है।

अगर मोदी प्रधानमंत्री बने और 'मजबूती' दिखाने की मुहिम में अपने तौर-तरीकों से लगे तो इस देश की जनता को ही नहीं बल्कि सेना को भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी जी कपट से प्रधानमंत्री पद तो हथियाया जा सकता है पर बहादुर नहीं बना जा सकता।

हुड्डा भी चौटाला की राह पर

चौटाला, बंसीलाल और हुड्डा शासन में भी यही सब होता रहा है। पर अब शायद सब कुछ बिके हुए चमचों के माध्यम से करने की योजना बना ली गयी है। हर मुख्यमंत्री सोचता है कि वह सारा प्रपंच चालाकी से करके निकल जायेगा। चौटाला साहब भी यही सोचते थे; हुड्डा भी यही सोच रहे हैं। पर जब दोनों की राह एक है तो अंजाम अलग क्यों होंगे।

29 सितम्बर को नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की चुनावी सभा में समूचे गांधी परिवार को जिस तरह पानी पी-पी कर गालियां दी उसका सार भी यही था कि सारा गांधी-परिवार उस अवस्था को प्राप्त कर गया है कि उसे राजनीति के कूड़ेदान में ही जगह मिलनी चाहिए। राहुल की तरह ही मोदी भी यह बताना जरूरी नहीं समझे कि उनके अपने गुलदस्ते में कौन सी फूल हैं जो इस देश के वातावरण को ईमानदारी और सच्चाई की महक से भर देंगे।

क्या-क्या फेंकोगे कूड़ेदान में?

एक के हाथ कालिख पुते है तो दूसरे के खूनसने! वे अपने हाथों को तो कुड़ेदान में फ़ेक नहीं सकते। बस वक्त-बेवक्त किसी कानून को या किसी सहयोगी को दोसी ठहरा कर कूड़ेदान में फ़ेकते रहना उनकी आदत बन चुकी है। जनता कितनी ही मजबूर हो वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं।

आम आदमी पार्टी से एक मुलाकात

फ़रीदाबाद (म.मो.) *दिनांक 22 सितम्बर को 'आप' की स्थानीय इकाई से पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रम के बारे में इस संवाददाता तथा हिन्द मज़दूर सभा के स्थानीय नेताओं ने विस्तृत बातचीत की। इस इकाई के अध्यक्ष आभास चंदीला नहर-पार बड़ौली के मूल निवासी हैं। विलायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहीं से एम बी ए करके लौटे चंदीला दिल्ली स्थित एच डी एफ सी बैंक में उच्चाधिकारी थे। इस पत्र से त्यागपत्र देकर वे पूर्णरूप से 'आप' कार्यकर्ता हो गये।*

चंदीला ने बताया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को बदल कर भ्रष्टाचार मुक्त एक नई व्यवस्था को बनाना है। दिल्ली चुनाव उनके लिये एक लिटमस टैस्ट के समान है। यदि वे यहां जीत जाते हैं तो वे एक अच्छी पार्टी के रूप में पहचाने जायेंगे। बातचीत के दौरान उनके एक साथी ने कहा कि वे सब तो जनलोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे।

सरकार ने उनकी जायज एवं साधारण सी मांग मानने की बजाय उन्हें उपदेश दिया कि कानून, भीड़ द्वारा सड़कों पर नहीं, संसद और विधान-सभाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाये जाते हैं। इसके साथ-साथ चैलेंज दिया कि दम है तो इन संस्थाओं में आकर कानून बनाओ। बस इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए 'आप' का गठन किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यदि आज भी सरकार जन-लोकपाल बना दे तो वे इस पार्टी को भंग कर देंगे।

'आप' कार्यकर्ताओं के विचार सुनकर सवाल उठने लाजमी थे। उनसे जब यह पूछा गया कि वे व्यवस्था-परिवर्तन करना चाहते हैं या सत्ता परिवर्तन?

यदि व्यवस्था परिवर्तन तो कौन सी व्यवस्था-समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी इत्यदि? सरकार की कैसी प्रणाली-लोकतान्त्रिक, तानाशाही, संसदीय अथवा राष्ट्रपति प्रणाली? जवाब में चंदीला ने कहा कि वे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिये लोकतान्त्रिक प्रणाली ही रखेंगे। वे तो केवल इसे भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्था-परिवर्तन की बजाय व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। शोषण की व्यवस्था तो यही रहेगी लेकिन ईमानदारी के साथ।

इस संवाददाता के स्वर में स्वर मिलाकर मौजूद हिन्द मज़दूर सभा के नेता एस डी त्यागी व सुरेन्द्र लाल ने भी कहा कि उन्होंने जे पी आन्दोलन भी न केवल देखा है बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी निभाई थी। जे पी भी भ्रष्टाचार मुक्त एक नई व्यवस्था, सम्पूर्ण क्रान्ति आदि की बात कहते थे। लेकिन उस आन्दोलन से पैदा हुए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नितीश कुमार , रामविलास पासवान, एन टी रामाराओ तथा देवीलाल जैसे भ्रष्ट एवं कुनबापरस्त। इसके अलावा कोई चुनाव जीत लेना किसी पार्टी के अच्छा या बुरा होने को प्रभावित नहीं करता। सन् 1977 में देवी लाल हरियाणा विधान सभा की 80 में से 76 सीटें जीत कर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ढाई साल में ही उनका शिराजा बिखर गया।

ज़न लोकपाल बना दिया जाय तो आम आदमी पार्टी को भंग कर देने की बात पर चौंकते हुए इस संवाददाता ने पूछा कि क्या लोक पाल से तमाम समस्यायें हल हो जायेगी? कदाचित नहीं।

पूरे वार्तालाप से निष्कर्ष यह निकला कि 'आप' पार्टी के पास यद्यपि कोई राजनीतिक दर्शन (फ़िलॉसफ़ी) तो नहीं है लेकिन फ़िर भी इसी व्यवस्था में रहते हुए मौजूदा एवं स्थापित भ्रष्ट राजनीतिक दलों एवं नेताओं को ललकारने का काम तो कर ही रही है। सत्तारूढ होने के बाद में लोग किस तरह से भ्रष्टाचार व शोषण से आम आदमी को मुक्ति दिलायेंगे, बाद में देखा जायेगा।